KISAN PLUS TV | KISAN PLUS Radio

टाइटल कोड - MPHIN7675

Email- haldharkisankgn@gmail.com

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

वर्ष 01 अंक 04 | जून 2022 | पृष्ठ-8 मूल्य -5.00 रुपये

यूरिया की एक बोरी जितनी ताकत, अब एक बोतल में : पीएम मोदी

गुजरात में देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट उद्घाटन पर पीएम बोले. हमने काम चलाऊ उपाय नहीं, समस्याओं का स्थायी समाधान खोजा

हलधर किसान।(प्रदेश समाचार)प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम में शामिल होकर कलोल स्थित इफको में निर्मित नैनो यूरिया (तरल) संयंत्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा. आज आत्मनिर्भर कृषि के लिए देश पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन करते हुए मैं विशेष आनंद की अनुभूति करता हूं। अब यूरिया की एक बोरी की जितनी ताकत है, वो एक बोतल में समाहित है। नैनो यूरिया की करीब आधा लीटर बोतल, किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार को गांवों के स्वावलंबन का बहुत बड़ा माध्यम बताया और कहा कि इसी में आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गांवों का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है, इसलिए पूज्य बापू और सरदार पटेल ने हमें जो रास्ता दिखाया, उसके अनुसार आज हम आदर्श सहकारी गांव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा 2014 में सरकार बनने के बाद हमने यूरिया की शत.प्रतिशत नीम कोटिंग का काम किया। इससे देश के किसानों को पर्याप्त यूरिया मिलना सुनिश्चित हुआ।

बड़ी फैक्ट्रियां को फिर कराया शुरु

पीएम मोदी ने कहा कि 7.8 साल पहले तक हमारे यहां ज्यादातर यूरिया खेत में जाने के बजाए कालाबाजारी का शिकार हो जाता था और किसान अपनी जरूरत के लिए लाठियां खाने को मजबूर होता था। हमारे यहां बड़ी फैक्ट्रियां भी नई तकनीक के अभाव में बंद हो गई थी। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने यूरिया की शत.प्रतिशत नीम कोटिंग का काम किया। इससे देश के किसानों को पर्याप्त यूरिया मिलना सुनिश्चित हुआ। साथ ही हमने यूपीए बिहारए झारखंडए ओडिशा और तेलंगाना में 5 बंद पड़े खाद कारखानों को फिर चालू करने का काम शुरु किया।

किसानों को 3500 की बोरी 300 में दे रही सरकार

पीएम ने बताया कि भारत विदेशों से जो यूरिया मंगाता है इसमें यूरिया का 50 किलो का एक बैग 3500 रुपए का पड़ता है। लेकिन देश में, किसान को वही यूरिया का बैग सिर्फ300 रुपए का दिया जाता है। यानी यूरिया के एक बैग पर हमारी सरकार 3.200 रुपए का भार वहन करती है। देश के किसान के हित में जो भी जरूरी हो, वो हम करते हैं, करेंगे और देश के किसानों की ताकत बढ़ाते रहेंगे।

पीएम मोदी ने सहकारिता को दिलाई पहचान : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता गुजरात की पहचान है। गुजरात ने सहकारिता के क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ाया है। सरदार पटेल और त्रिभुवनभाई पटेल ने मिलकर अमूल की नींव रखी, जो आज सहकारिता का श्रेष्ठ उदाहरण है। पहले सहकारिता को कोई मान्यता नहीं थी। लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में एक अलग मंत्रालय का गठन कर इसे पहचान दी। देश में सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य पालन, महिला सहकारी समितियां, दुग्ध उत्पादक समितियों का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। गांधीनगर और देश के अन्य शहरों में आर्गेनिक लैब की स्थापना होगी, ताकि लोगों को प्रमाणित आर्गेनिक उत्पाद मिल सके। केंद्र ने किसानों, गन्ना उत्पादकों और सहकारिता क्षेत्र पर लगने वाले करों को 1 2 से घटाकर सात प्रतिशत तक कर दिया है। बजट में किसानों के लिए आठ हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल है सहकार

पीएम मोदी ने कहा. आत्मनिर्भरता में भारत की अनेक मुश्किलों का हल है। आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल, सहकार है, ये हमने गुजरात में बहुत सफलता के साथ अनुभव किया है और आप सभी साथी इस सफलता के सेनानी हैं, डेयरी सेक्टर के कोऑपरेटिव मॉडल का उदाहरण हमारे सामने है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जिसमें गुजरात की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। बीते सालों में डेयरी सेक्टर तेजी से बढ़ भी रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। गुजरात में दूध आधारित उद्योगों का व्यापक प्रसार इसलिए हुआ, क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से पाबंदियां कम से कम रहीं। सरकार जितना बच सके बचने की कोशिश करती है और सहकारी क्षेत्र को फलने-फूलने की आजादी देती है। सरकार यहां सिर्फएक सहायक की भूमिका निभाती है, बाकी का काम या तो आप जैसे सहकार करते हैं, किसान करते हैं।

प्लांट की क्षमता 1.5 लाख बॉटल प्रतिदिन

कलोल में नैनो यूरिया (लिक्विड)प्लांट 175 करोड़ रुपए में बना है। प्लांट की क्षमता आधा लीटर की 1.5 लाख बॉटल प्रतिदिन की है। ऐसे 8 और प्लांट देशभर में लगाए जाएंगे। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नैनो यूरिया प्लांट आज से चालू हो गया है। मोदी सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। गुजरात में सहयोग मॉडल सफल रहा है। सहकारी क्षेत्र में शामिल होने के बाद से एक अलग विभाग की मांग की जा रही थी। इसी के चलते सत्ता में मोदी सरकार के आने के बाद अलग मंत्रालय का गठन किया गया है।

किसान को होगा फायदा

इफको के चीफ फील्ड मैनेजर बृजवीर सिंह ने बताया कि नैनो यूरिया लिक्विड की आधा लीटर की एक बोतल में 40.000 पीपीएम नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की यह मात्रा सामान्य यूरिया के 45 किलोग्राम के एक बैग के बराबर होती है। एक बैग यूरिया में 46 परसेंट नाइट्रोजन होता है। लेकिन यूरिया का छिड़काव करने से नाइट्रोजन की पूरी मात्रा पौधों को नहीं मिल पाती है। किसान पौधों की बढ़वार के लिए ज्यादा मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैंए इससे फसल की लागत तो बढ़ती ही है साथ में पर्यावरण को भी नुकसान होता है। एक एकड़ खेत में 150 लीटर पानी में नैनो यूरिया की एक बोतल का घोल बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। घोल के रूप में यूरिया देने से पौधों को पूरी मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है। नैनो यूरिया के ट्रायल के दौरान फसलों में 8 से 25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

240 रुपए में मिलेगी बोतल

नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल की कीमत 240 रुपये है। यह एक एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। जबकि यूरिया के एक बैग की वर्तमान कीमत 266.50 रुपये है और ज्यादातर किसान एक एकड़ खेत में एक से अधिक यूरिया बैग का इस्तेमाल करते हैं। नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसान को पैसे की बचत तो होगी ही साथ ही पैदावार ज्यादा मिलेगी और पर्यावरण महफूज रहेगा।

संपादकीय...

कृषि एक व्यवसाय ही नही, एक विज्ञान

भारत के परंपरागत परिदृश्य में कृषि एक व्यवसाय ही नही, वह एक विज्ञान, एक जीवन शैली और सबसे बढ़ कर एक संस्कृति भी है। यही वजह है कि भारत में बहुत से लोग अन्न को ब्रह्म का रूप मानते हैं।अगर हम अपनी कृषि संस्कृति के परंपरागत स्रोतों को खोजने का प्रयास करेंगे, तो पाएंगे कि वहां कृषि केवल वन संपदा के विनाश से ताल्लुक रखने वाली सभ्यता नहीं है, जैसा कि उसे पश्चिमी विद्वानों द्वारा देखा.दिखाया जाता रहा है।इसके बजाय वह प्रकृति.पूरक विकास की ओर बढ़ने की संभावनाओं से युक्त एक संस्कृति भी है।पर हुआ यह है कि सभ्यता जनित तीव्र विकास की हड़बड़ी ने मानव जाति के मनो.मस्तिष्क को इस कदर जकड़ लिया है कि कृषि से ताल्लुक रखने वाला उसका सांस्कृतिक पक्ष गौण होकर पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है।

इसके बावजूद मौजूदा दौर में ऐसे हालात सामने आ रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति के बीच की यह जद्दोजहद सतह पर आ गई है। हमारा समाज अन्न को पवित्र बताता है और उसे सबके साथ बांट कर खाने के लिए लंगर जैसी प्रथा को अपना आदर्श मानता है। मगर जिस तरह की नई बाजार व्यवस्था पनप रही हैए उसमें अब यह संस्कृति और इससे जुड़ी सोच संकटग्रस्त होती जाती है। पर भारत जैसे देश में इस सांस्कृतिक चेतना का समूलोच्छेदन संभव नहीं है। इसकी वजह है कि इस चेतना की जड़ें हमारे उस सांस्कृतिक इतिहास में हैं, जो वेदों के समय से लेकर अभी तक जीवंत हैं।

अन्न को ब्रह्म के पर्याय के रूप में देखने की वजह से वह जीवन के आधार और प्राकृतिक संसाधनों के सार की तरह हमारे सामने उपस्थित होता है। इस सांस्कृतिक चेतना की वजह से अन्न के व्यावसायिक रूपों को, अन्न के प्राकृतिक और दैवी रूपों में दखल की तरह देखा जाता है।इस तरह अन्न समाज में अनेक नैतिक मूल्यों के आधार के रूप में हमारे सामने आता है।किसान को उन नैतिक मूल्यों के स्रोत के रूप में देखने की वजह से, मात्र एक व्यवसायी की तरह न देखते हुए 'अन्नदाता' की तरह देखा जाने लगता है।

प्राचीन काल में कृषि संस्कृति अपने भौतिक आधार से आध्यात्मिक आयाम तक स्वाभाविक रूप में विकास करती दिखाई देती है।उस काल तक अन्न का भौतिक संसार अपनी गहराई में ब्रह्म से जुड़े गहरे स्तरों को अपने भीतर ही छिपाए रहता है। तैत्तीरियोपनिषद में भृगु आपने पिता वरुण से कहते हैं कि उन्होंने जान लिया है कि अन्न ही ब्रह्म है। तब वे अपने पुत्र को अन्न के और गहरे स्तरों में उतरने के लिए कहते हैं।सिलसिलेवार तरीके से भीतर उतरते हुए भृगु अन्न से प्राण तक जाते हैं, फ़िर प्राण से मन तक पहुंचते हैंए मन से विज्ञान तक और अंत में आनंद तक का सफ़र तय करते हैं। ब्रह्म अपने भौतिक अस्तित्व में अन्न के रूप में प्रकट होकर जीवन को गतिमान करता है और अपने गहरे स्तर में आनंद की अनुभूति के रूप में सामने आता है।

इसी तरह कृषक पृथ्वी पर एक श्रमिक की तरह अन्न उपजाता हुआ भीए स्वर्ग के देवों के पर्याय के रूप में हमारे सामने रहता है। वेदों में किसानी से जुड़े हुए देवता इंद्र, वरुण और पूषा हैं, जिन्हें किसानों के स्व.भाव का पर्याय कह सकते हैं।किसान उन देवों के पार्थिव प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने रहते हैं।संभवतः इसीलिए इंद्र का नाम आज भी उत्तर भारत के जाट बहुल किसानों में अपनी निरंतरता बनाए हुए है।इससे यह साबित होता है कि भारतीय संस्कृति अपने वैदिक काल से लेकर हमारे समय तक कृषक समाज की चेतना का नियमन करती आ रही है।

उपनिषद काल के बाद प्रकट हुए अनेक दर्शन कृषि से संबंधित विविध धारणाओं को गहरे अर्थ की व्यंजना करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। योग दर्शन कहता है कि मनुष्य के कर्म के संसार में अगर किसी को कर्मों के प्रसवित होते रहने की स्थिति से निजात चाहिएए तो उसे प्रति.प्रसव द्वारा निर्बीज समाधि् तक जाना होगा।हम देख सकते हैं कि यह पूरी शब्दावली किस कदर खेती.बाड़ी से जुड़ी हुई है। बाद में कृषि को विज्ञान के रूप में विकसित करने के प्रयास भी हुए।जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौजूद अनेक सूत्रों में दिखाई देता है। वहां ष्मधु और शकुद लेपन सेष् बीजों की बेहतर फसल देने की क्षमता के विकास की बात की गई है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पराशर ऋषि द्वारा रचित 'कृषि पराशर' नामक ग्रंथ मिलता है, जो खेतीबाड़ी के वैज्ञानिक विकास का ग्रंथ है।इसके अलावा कश्यप ऋषि का 'कृषि सूक्त' भी कृषि को विज्ञान की तरह ग्रहण करने की दिशा में आगे बढ़ता है। मध्यकाल का जो परिदृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है, उसमें कृषि के इस भौतिक और वैज्ञानिक पक्ष के बजाय, उसके आदर्शीकरण और प्रतीकीकरण की बात अधिक सामने आती है।दूसरा फर्क यह पड़ता है कि मध्यकाल तक व्यापारिक पूंजी के उदय के कारण, कृषि से मुनाफ़ा कमाने की प्रवृत्ति जोर पकड़ती है।

प्रतियां पाने, लेख प्रकाशन के लिए संपर्क करें

हलधर किसान, राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र की प्रतिया प्राप्त करने के लिए अपना नाम, डाक पता और फोन नंबर सहित संपर्क करें। साथ ही कृषि, पशुपालन, बागवानी, अनुसंधान जैसे क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, शोध, खेती में नवाचार जैसे लेख प्रकाशन कराना चाहते है तो हमें वाट्सएप नंबर– 8305103633, 94254 89337 पर भेजे सकते है। हम आपका लेख प्रमुखता से फोटो सहित उचित स्थान पर प्रकाशित करेंगे।

प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का क्यों विरोध कर रहे हैं मछुआरे और किसान

मुंबई से लगे पालघर जिले के समुद्री तट पर बन रही बंदरगाह की वजह से एक लाख से अधिक लोगों के प्रभावित होने का मंडरा रहा खतरा

हलधर किसान। (प्रदेश समाचार) महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगे पालघर जिले के समुद्री तट पर स्थित और पर्यावरण के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र वाढवण में बंदरगाह निर्माण को लेकर स्थानीय लोग नाराज नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि इस परियोजना के अंतर्गत पर्यावरण को होने वाले नुकसान का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया।

विरोध का दूसरा कारण यह है कि जैव विविधता और मछुआरों तथा किसानों की आजीविका की दृष्टि से यह पूरी पट्टी 'गोल्डन बेल्ट' के नाम से जानी जाती है और परियोजना के निर्माण से लगभग एक लाख परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। इस परियोजना का प्रभाव 13 गांवों पर पड़ेगा और यहां की करीब चालीस प्रतिशत आबादी के सामने रोजीरोटी का संकट खड़ा होगा।

उल्लेखनीय है कि कि वाढवण स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की यह बंदरगाह परियोजना पांच हजार एकड़ समुद्री क्षेत्र में स्थापित की जा रही है। इसके तहत समुद्र तट से चार किलोमीटर लंबा और 20 मीटर गहरा एक ढांचा तैयार किया जाएगा। वर्ष 2028 तक कुल 38 माल गोदाम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यहां से कोयलाए सीमेंट, रसायन और तेल आदि चीजों का सालाना 132 मिलियन टन माल का परिवहन किया जा सकता है। इस बंदरगाह के लिए 350 किलोमीटर लंबी सड़क और 12 किलोमीटर लंबी रेललाइन का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 1995 में एक निजी कंपनी ने पहले भी इस परियोजना का निर्माण शुरू किया था। लेकिन, तब भी भारी जनविरोध के कारण तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना का काम रोक दिया गया था। इसके अलावा डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण ने परियोजना के खिलाफ दायर एक याचिका पर निर्णय लेते हुए वर्ष 1998 में इस बंदरगाह के निर्माण को स्थगित कर दिया था। उसके बाद वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'ड्रीम प्रोजेक्ट' बताया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट 74%और महाराष्ट्र सागर मंडल 26% की भागीदारी से 65 हजार करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू करने की मंशा जाहिर की गई। परियोजना समर्थकों का तर्क है कि प्रस्तावित बंदरगाह 24 घंटे चालू रहेगा, इसलिए पूरे क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।

परियोजना का विरोध कर रही वाढवण की सरपंच हेमलता बालाशी बताती हैं, यह परियोजना पारंपरिक कृषि, बागवानी और मछलीपालन से जुड़े एक लाख परिवारों के लिए नुकसानदायक साबित होगी। स्थानीय लोगों ने कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक संघर्ष समिति बनाई है। इस समिति के बैनर पर हम सभी इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।

इसके अलावा परियोजना के विरोध का प्रमुख आधार जैव विविधता के लिए का खतरा बताया जा रहा है। खासकर अनेक तरह की मछलियों को ध्यान में रखते हुए यह समुद्री क्षेत्र जलीय जीव.जंतुओं का घर माना जाता है। ऐसे में यदि यहां बंदरगाह बनाया जाता है तो सबसे बुरा असर एक दर्जन से अधिक गांवों के मछुआरों की आजीविका पर पड़ेगा। दरअसल, समुद्र की इस पट्टी पर चट्टानें हैं इसलिए मछली की कई प्रजातियां प्रजनन के लिए यहां आती हैं। यही वजह है कि बंदरगाह बनने के बाद आने वाले समय में ऐसी मछलियों की प्रजनन प्रक्रिया और उनकी उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। दूसरी आशंका यह है कि मालवाहक नावों से निकलने वाला ज्वार का पानी खाड़ी क्षेत्र में घुसपैठ करेगा और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाएगा।

अर्नाला मच्छीमार संस्था के उपाध्यक्ष हिराजी तारे बताते हैं, ष्इससे मछली पालन का पूरा व्यवसाय ध्वस्त हो जाएगा, पूरे इलाके की समृद्ध खेती खत्म हो

जाएगी। वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस परियोजना को लेकर उनसे कोई राय नहीं ली गई है। इनका यह भी कहना है कि पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1991 से इस पूरे क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसकी वजह से यहां विकास से जुड़ी कई परियोजना पहले से ही लंबित हैं। हालांकिए बंदरगाह परियोजना को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसे उद्योग के रूप में नहीं गिनने का फैसला लिया है। इसके अलावाए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया में परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को अनुमति देने के लिए भी उसे मौलिक रूप से बदल दिया गया है।

एक स्थानीय रहवासी नरेन्द्र पाटिल बताते हैं यहां के लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर एंटी पोर्ट जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यहां के किसानों और मछुआरों को स्थानीय व्यापारियों का भी साथ मिल रहा है।

समर्थन मूल्य पर 44 लाख 45 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का हुआ उपार्जन - खाद्य मंत्री श्री सिंह

हलधर किसान।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया है कि प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 222.23 में समर्थन मूल्य पर 5 लाख 72 हजार 154 किसानों से 44 लाख 45 हजार 937 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है।गेहूँ उपार्जन का कार्य 31 मई 222 तक किया जाएगा।समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय करने वाले 4 लाख 41 हजार 125 किसानों को 6 हजार 787 करोड़ रुपए का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन किया जा चुका है।शेष किसानों के भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने बताया कि भुगतान प्रक्रिया को सहज और सरल बनाने के उद्देश्य से समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय करने वाले ऐसे किसान, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, खाता बंद है, जनधन के खाते में लिमिट निहित है या खातेदार की मृत्यु होने आदि कारणों से भुगतान लंबित है, अपना बैंक खाता उपार्जन केंद्र, जिला सहकारी एवं केंद्रीय बैंक और जिला खाद्य कार्यालय में पोर्टल पर एंट्री करवाएँ, जिससे उनके बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जा सके। किसान स्वयं पोर्टल पर रबी 2022 .23 पर किसान की जानकारी के विकल्प पर अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर भुगतान की स्थिति देख सकते हैं। पोर्टल पर किसान अपना पंजीयन कोड दर्ज कर राशि के भुगतान के सफ़ल या असफ़ल होने की स्थिति और किन कारणों से भुगतान असफ़ल हुआ है, की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान असफ़ल होने की स्थिति में किसानों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस से अवगत भी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को समर्थन मूल्य पर राशि का भुगतान किस बैंक के अकाउंट में किया गया है इसकी जानकारी उपलब्ध है।

पारंपरिक फसलों के संरक्षण के बावजूद अभी भी कई फसलें विलुप्ति के कगार पर

अध्ययनकर्ताओं की एक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह (सीजीआईएआर) के केंद्रों की यात्रा में तीन साल बिताए, जिनमें से हर एक ने गेहूं, धान, मक्का, आलू, बीन्स और कसावा जैसी फसलों के विशाल जीन बैंक संग्रह बनाए। उन्होंने इस बात का आकलन किया कि इस तरह के संग्रह किस हद तक अलग.अलग तरह की कृषि भूमि के लिए सही होंगे। दुनिया भर के जीन बैंकों में 25 प्रमुख फसलों की पारंपरिक किस्मों के वैश्विक विश्लेषण से पता चला है कि उनके संरक्षण की दिशा में आधी सदी से भी अधिक समय में जबरदस्त प्रगति हुई है। जबकि इनमें सबसे महत्वपूर्ण किस्मों की पहचान भी की गई है। अभी भी फसलों की कई किस्मों को सामने लाना बाकी है। यह अध्ययन कॉलिन खौरी की अगुवाई में किया गया है। खौरी एलायंस ऑफबायोवर्सिटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के शोधकर्ता और सैन डिएगो बोटैनिकल गार्डन में विज्ञान और संरक्षण के निदेशक हैं।

अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि ये प्रजातियां उनके जंगली रिश्तेदारों से मेल खाती हैं। फसल उगाने वालों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक हैं। क्योंकि प्रत्येक बीज में विशेष कीटों और रोगों के प्रतिरोध, सूखे या गर्मी या ठंड या नमकीन मिट्टी में उगने और विभिन्न स्वाद और पोषण सहित इनमें कई लक्षण होते हैं। पिछले 100 वर्षों में दुनिया भर में हुए भारी पर्यावरणीय और सामाजिक बदलावों के कारणए कई किसान अब इन किस्मों को नहीं उगाते हैं और कई आवास जहां इन फसलों के जंगली रिश्तेदार कभी रहते थे अब वे पूरी तरह से बदल गए हैं।

पिछले 50 वर्षों में बीजों के संरक्षण को सुनिश्चित करने और फसल प्रजनन उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जीन बैंकों का उपयोग किया गया। जीन बैंकों में बीजों के रखरखाव करने के लिए व्यापक वैश्विक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों ने अंतरराष्ट्रीय जीन बैंकों की स्थापना के साथ.साथ राष्ट्रीयए क्षेत्रीय और अन्य संग्रहों की स्थापना की। इन जीन बैंकों में से एक फ्यूचर सीड्स है, जिसका उद्घाटन कोलंबिया के पामिरा में हुआ था। हालांकि ये प्रयास किस हद तक फसलों की प्रजातियों को इकट्ठा करने और संरक्षित करने में सफल रहे हैं, इसका मूल्यांकन पहले नहीं किया गया। फसल उनके जंगली रिश्तेदारों के जीन बैंकों का एक वैश्विक विश्लेषण 2016 में पूरा किया गया थाए जिसे नेचर प्लांट्स में भी प्रकाशित किया गया था। भू.प्रजातियों पर यह नया शोध दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से 25 के भीतर आनुवंशिक विविधता के संरक्षण करना है।

खौरी ने कहा कि अब हम जो जानते हैं वह यह है कि पारंपरिक किसानों की फसल की किस्मों की विविधता का लगभग दो तिहाई, औसतन हमने जिन 25 फसलों का अध्ययन किया है, वे पहले से ही जीन बैंकों में रखी गई हैं। अध्ययन में पाया गया कि ब्रेडफ्रूट, केला और प्लाण्टेंस, दाल, कॉमन बीन्स, चिकपीस, जौ और गेहूं जैसी फसलें भूमि की विविधता के मामले में जीन बैंकों में सबसे अधिक संरक्षित की गई हैं, जबकि फसलों की सबसे बड़ी संरक्षण की कमी हमेशा बनी रहती है।

अध्ययन में इन 25 फसलों के लिए भूमि में सबसे बड़ी विविधता वाले दुनिया के क्षेत्रों की भी पहचान की गई, जिसमें बांग्लादेश, इथियोपिया, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के साथ.साथ दक्षिण अफ्रीका, मध्य एशिया, भूमध्यसागरीय, पश्चिम एशिया के क्षेत्र, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के इंडियन पर्वत और मेसोअमेरिका के इलाके शामिल थे।

खौरी ने कहा दुनिया के फसल संरक्षणवादियों ने पिछली आधी सदी में बहुत काम किया है और अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। लेकिन मुझे यह जानकर राहत मिली कि जीन बैंकों में फसल विविधता का संरक्षण हमारे मुकाबले कहीं आगे की सोच रखती है। हालांकि यह कहते हुए कि केवल जीन बैंकों में फसलों का भंडारण करना पर्याप्त नहीं है। फसलों को कीटों और बीमारियों और जलवायु परिवर्तन के साथ विकसित करना जारी रखने के लिए, अलग.अलग तरह की फसलों की खेती करना आवश्यकता है।

कमी किस तरह हो पूरी

इस शोध के परिणामों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय भागीदारों को शामिल करने की योजना के लिए किया जा रहा है। जो वर्तमान में महत्वपूर्ण संरक्षण वाले 10 देशों में एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जंगली रिश्तेदारों पर पिछले शोध के साथए जिसमें 2015.2021 तक जीन बैंकों में संरक्षण के लिए 4.500 से अधिक नए नमूनों के संग्रह की योजना बनाने में मदद कीए आगामी कुछ वर्षों में भूमि के काफी संग्रह के लिए उम्मीदें बहुत अधिक हैं। अध्ययनकर्ता ने कहा अभियान शुरू करने से पहले, हमें यह जानने की जरूरत है कि हमने पहले किसी फसल को कहां एकत्र किया है और फसलों की विविधता में अभी भी कहां कमी है। नाइजर में आईसीआरआईएसएटी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां लोबिया, बाजरा और ज्वार में जबरदस्त विविधता है।

एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सीआईएटी में आनुवंशिक संसाधन वैज्ञानिक जूली सरडोस, जो छह वर्षों से अधिक समय से केला संग्रह मिशन चला रही हैं, कहती हैं कि उनके काम का एक उल्लेखनीय उदाहरण कुक आइलैंड्स में केले है, जिसे उन्होंने 2019 में एकत्र किया था।

उन्होंने बताया कई किसान जिनसे हम मिलते हैंए वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनके कुछ पारंपरिक भू.प्रजातियां उत्तरोत्तर लुप्त होती जा रही हैं, ज्यादातर जलवायु और सामाजिक कारकों से जुड़े परिवर्तनों से फी केला एक प्रतिष्ठित पोलिनेशियन फसल है जिसमें बड़ी क्षमता है। उनके संतरे के फलों में प्रो.विटामिन ए का स्तर बहुत अधिक होता है। उन्होंने कहा लेकिन कुक आइलैंड्स में हमने जो फी केले का बीज एकत्र किया था, उनमें से प्रत्येक की खेती केवल एक व्यक्ति द्वारा की जा रही थी, ज्यादातर मृतक रिश्तेदार की याद में और ये किसान अपने पूर्वजों की विरासत को गायब होते हुए देखकर चिंतित थे। एक जोड़े के बाद वहां केले इकट्ठा करने के दिनों में, मैंने उनकी चिंताओं को भी साझा कियाए जिन युवाओं से हम मिले उनमें से अधिकांश को बमुश्किल पता था कि 'फी' केले खाने योग्य है। यह अध्ययन नेचर प्लांट्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

दो से तीन गुणा महंगा बिक रहा है भूसा, राज्य सरकारें लगा रही हैं प्रतिबंध

हलधर किसान। बढ़ती महंगाई का असर खाने. पीने, पेट्रोलियम पदार्थों के साथ ही खेती. किसानी, पशुपालन पर भी पड़ रहा है। खरीफ सीजन में कई राज्यों में बुआई के साथ.साथ गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, जिसके चलते देश में भूसे का संकट खड़ा हो गया है।

सिर्फआप के खाने की चीजों पर ही महंगाई की मार नहीं पड़ी है। पशुओं के चारे पर भी संकट है, भूसा पिछले साल दो से तीन गुना रेट पर बिक रहा है। पिछले साल जो भूसा 400.600 रुपए क्विंटल था, वो इस बार सीजन में ही 1100.1700 रुपए के बीच बिक रहा है। राजस्थान के बीकानेर में गेहूं का भूसा 2000 रुपए कुंटल तक पहुंच गया है।

मथुरा के मोडलिया गांव के किसान अजय कुमार के पास 4 भैंसे हैं। अजय बताते हैं, मैंने पिछले महीने 550 रुपए मन (40 किलो) भूसा लिया, जबकि पिछले साल यही भूसा 150.200 रुपए मन था, यानि तीन गुना महंगा हो गया है। हालत ये हैं कि अब भूसा मिल ही नहीं रहा। मेरी समझ से इधर सरसों की खेती ज्यादा हुई और गेहूं कमए इसलिए भूसा महंगा हो गया।

मथुरा में ही राजस्थान की सीमा से सटे मांट इलाके के बाजना गांव के किसान शिवकुमार के मुताबिक उनके जिले में इस बार सीजन में ही 1200.1300 रुपए का रेट था, जबकि पिछली बार अच्छा भूसा 600.800 में मिला था। शिवकुमार कहते हैं, भूसा तो खोजना पड़ रहा है। हमारा इलाका राजस्थान से लगा है तो वहां बहुत सप्लाई होती है लेकिन इस बार डीएम ने मार्च में ही आदेश जारी कर दिया, कि भूसा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि गोशाला वाले भूसा न मिलने की शिकायत कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इसका विरोध किया, आखिर किसान की सारी फसलें तो सस्ती बिकती हैं, पहली बार भूसा सही जा रहा है तो किसान क्यों न बेचे?

गेहूं की पैदावार कम होने कई राज्यों में पशु चारे का संकट सीजन में खड़ा हो गया है। जिससे निपटने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने दूसरे राज्यों को भूसा भेजने में पूर्ण या आशिंक.मौखिक प्रतिबंध लगा रखा है। यहां तक की यूपी के मैनपुरी जिले में जिलाधिकारी ने मई के पहले हफ्ते में जिले से बाहर भूसा जाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। भूसे की महंगाई के पीछे मुख्य वजह गेहूं का कम उत्पादन बताया जा रहा है। किसान कृषि वैज्ञानिक और जानकारों के मुताबिक पिछले साल सरसों की कीमतें अच्छी होने के चलते इस बार यूपी, राजस्थान,हरियाणा समेत कई राज्यों में किसानों ने सरसों की ज्यादा बुवाई की। दूसरी वजह मार्च में एकाएक गर्मी बढ़ने से गेहूं का कम उत्पादन भी है।

राजस्थान में किसानों के मुताबिक यहां कहीं भूसा है ही नहीं, जो है वो 20 रुपए किलो के ऊपर है। हमारे इलाके में ज्यादातर किसान गाय पालते हैं। भूसे की किल्लत की तत्कालिक वजह तो हरियाणा.पंजाब से भूसे का न आना है लेकिन लंबी अविधि में इसके लिए पानी की किल्लत और मौसम जिम्मेदार है। सिंचाई की समस्या के चलते गेहूं तो बहुत कम होने लगा है। पिछले साल कम बारिश के चलते हमारे यहां ज्वार भी नहीं हो पाई, वर्ना इस सीजन में पशु वही खा लेते।

हिमाचल प्रदेश: कृषि और पशु वैज्ञानिकों के मुताबिक एक गाय और भैंस को औसतन 4.8 किलो भूसा चाहिए। हरा चारा न होने की दशा में ये मात्रा बढ़ भी सकती है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक डॉ. पुतान सिंह कहते हैं, श्भारत में भूसा पशुओं के चारे का प्रमुख स्त्रोत है। वैसे तो 10 लीटर दूध देने वाली एक भैंस को दिनभर में औसतन 30 किलो चारा चाहिए इसमें 4 किलो दाना, 4.5 किलो भूसा और बाकी हरा चारा होना चाहिए, लेकिन हरा चारा न होने पर किसान भूसे पर निर्भर हो जाते हैं। पशुओं का चारा उनके वजन और उपयोगिता पर निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश: पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. वीके सिंह ने कहा. चारा कम होने का सबसे बड़ा कारण है मशीनीकरण, कंबाइन से गेहूं कटने बहुत कम किसान भूसा नहीं बनवाते हैं। दूसरा कई बार किसान खेत जला देता है तो दूसरे पशुओं के चरने का नहीं मिलता है। इसके अलावा घटती जोत के चलते किसान अब अनाज या फल.सब्जी उगाने को प्राथमिकता देता है। और जो पशुचारागाह हैं उन पर कई जगह कब्जे हो गए हैं उन्हें छुड़ाने की प्रक्रिया चल रही है।

उत्तराखंड: मई को जारी अपने एक आदेश में उत्तराखंड के पशुपालन विभाग ने राज्य से बाहर भूसा भेजने, भूसे का ईंट भट्टे में उपयोग रोकने, पराली न जालने के आदेश जारी किए। पशुपालन विभाग के सचिव डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि हरियाणा समेत कई राज्यों में भूसे को बाहर भेजने से प्रतिबंध लगाए जाने के कारण भूसे का औसत भाव जो सीजन में 400.600 रहता था वो 900 से 1300 रुपए कुंटल पहुंच गया है।

भारत में ज्यादातर पशुपालन उत्तर भारत के यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होता है। और इन्हीं राज्यों में ज्यादा गेहूं की पैदावार भी होती है। आंकड़ों की बात करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में करीब 335.340 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है, साल 2021.22 में रबी सीजन में करीब 334 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती हुई थीए जिसमें सरकार को 11.13 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान था, खाद्य विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने पिछले दिनों बताया कि कृषि मंत्रालय ने संसोधित अनुमान में गेहूं उत्पादन 10.5 करोड़ टन किया है।

दुनिया के सबसे ज्यादा किसानों और पशुओं वाले देश भारत में कुल पशुओं की संख्या 53.58 करोड़ है। साल 2019 में आई 20वीं पशुगणना के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा संख्या गोवंश और फिर भैंसों की है। इस तरह गौ और महिषवंशीय पशुओं की कुल संख्या करीब 30.23 करोड़ हो जाती है। यही वो पशु भी हैं जो सबसे ज्यादा चारा और खासकर भूसा खाते हैं। क्योंकि इसको लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है।

गुजरात पद्धति पर होगी मप्र में प्राकृतिक खेती: मुख्यमंत्री श्री चौहान

सफल प्रयोग देखने अध्ययन यात्रा पर जाएंगे मध्यप्रदेश के जन-प्रतिनिधि और किसान

हलधर किसान- (प्रादेशिक समाचार)। नवगठित प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड की मंत्रालय में हुई पहली बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि की प्राचीन पद्धति प्राकृतिक कृषि, भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। इस तरह की कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता। इस नाते पर्यावरण के लिए अनुकूल और देसी गाय के गोबर और गौमूत्र पर आधारित प्राकृतिक कृषि को मध्यप्रदेश में बढ़ावा दिया जाएगा।,मध्यप्रदेश में प्राकृतिक कृषि से संबंधित कार्यों को गुजरात पैटर्न पर संचालित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक कृषि विकास योजना के प्रथम चरण के कार्यों को प्रारंभ किया जाए। हरियाणा और गुजरात राज्यों के बाद मध्यप्रदेश ने प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन कर लिया है। मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री कमल पटेल, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र.संस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी, अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं पशुपालन जेएन कंसोटिया एवं कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेंद्र सिंह और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का प्राकृतिक कृषि के लिए पूर्व में पंजीयन के लिए आहवान किया गया था। इसके बाद किसानों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिली। आगामी 31 मई तक प्राकृतिक कृषि के लिए जो कृषक गंभीर हैं उन्हें पंजीयन करवाने की सुविधा दी जाए। अब तक प्रदेश में करीब 25 हजार कृषकों ने प्राकृतिक कृषि में रुचि प्रदर्शित की है और इसके लिए पंजीयन भी करवा लिया है।

प्राकृतिक कृषि देखने जाएंगे मध्यप्रदेश के जन.प्रतिनिधि और किसान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के जन.प्रतिनिधिए कृषक और संबंधित अधिकारी हरियाणा एवं गुजरात का भ्रमण कर प्राकृतिक कृषि के सफल प्रयोगों को देखेंगे। इन राज्यों के अलावा भी कहीं प्राकृतिक खेती हो रही है तो उसकी अध्ययन यात्रा की जाएगी। श्री आचार्य देवव्रत के कार्य के परिणाम सबके सामने हैं। उनका अनुसरण करना ही बेहतर है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग प्राकृतिक कृषि के विकास में किया जाएगा। विशेषज्ञों की सेवाएँ लेने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

प्राकृतिक कृषि का कार्य प्रदेश के 5710 ग्रामों में प्रारंभ होगा। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में 100 ग्राम चयनित करने का लक्ष्य है। प्रेरक द्वारा 20.20 ग्राम चिन्हित कर दायित्व निभाया जाएगा। सर्वाधिक ग्राम इंदौर जिले में रहेंगे। इंदौर जिले के 610 ग्रामों में प्राकृतिक कृषि की तैयारी है। कृषि विभाग से आत्मा के जिला स्तरीय अमले का उपयोग प्राकृतिक कृषि के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अभी कुछ जिलों के कुछ ग्रामों में प्राकृतिक कृषि हो रही है। इनमें नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिले भी शामिल हैं। यहाँ हो रहे कार्य के अनुरूप अन्य ग्रामों तक प्राकृतिक कृषि का विस्तार करें। प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण देने के लिए कार्य करने वाले प्रेरकों के लिए प्रशिक्षण शेड्यूल बनाएँ। आत्मा का स्टाफ इस कार्य में संलग्न करने संबंधी कार्रवाई भी पूर्ण की जाए।

10 लाख से अधिक ले चुके हैं प्रशिक्षण

भोपाल में शून्य बजट, प्राकृतिक कृषि पद्धति विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत के ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने के लिए प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्री और किसान शामिल हुए थे। यह कार्यशाला 13 अप्रैल को हुई थी। प्रदेश में कुल 10.65 लाख प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण का लाभ वर्चुअली प्राप्त किया था। इसके बाद 18 से 20 मई को गुजरात सरकार ने मास्टर ट्रेनर्स की सहायता से मध्यप्रदेश के 52 जिलों में प्रशिक्षण शिविर लगाकर करीब 3 हजार अधिकारियों और कृषि विभाग के मैदानी अमले एवं 6 हजार 247 कृषकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया। बताया गया कि वर्तमान में 7.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि के लिए किसान आगे आए हैं। प्रत्येक जिले में प्रेरक मास्टर्स ट्रेनर्स की भूमिका निभाएंगे। मध्यप्रदेश में आगामी रबी सीजन से प्राकृतिक कृषि का रकबा निर्धारित किया जाएगा और किसानों को इसके लिए प्रेरित किया जाएगा।

किसान सम्मान निधि योजना में लाखों किसानों को हुआ फायदा

(हलधन किसान)। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, सोयाबीन अनुसंधान एवं विकास सोसायटीए सोलिडारिडाड, भोपाल और सोपा इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किये जा रहे सोया महाकुम्भ का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के ऑडिटोरियम में आज उदघाटन हुआ। उदघाटन समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कृषि मंत्री कमल पटेल, सचिव डेयर और महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, सांसद शंकर लालवानी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद.आईआईएसआर निदेशक डॉ. नीता खांडेकर और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पहले दिन सोयाबीन उत्पादक, वैज्ञानिक, विकास विभागों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 2500 लोगों ने भाग लिया।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने देश की अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से महामारी की स्थिति में कृषक समुदाय की कड़ी मेहनत और योगदान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कृषि के बजटीय आवंटन को बढ़ाकर एक लाख 32 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। यह 2014 के बाद से रिकॉर्ड वृद्धि है। इसमें से 65 हजार करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ के रूप में दिए जाते हैं, जिससे लगभग 50 लाख करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसान की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है।

किसान.कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसान कल्याण की योजनाएँ बनाकर उन्हें साकार रूप दिया गया है। किसान केंद्रित योजनाओं से किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि एमएसपी के माध्यम से खरीद की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है, जिससे राज्य के किसानों को लाभ हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 48 लाख किसानों को फसल बीमा योजना में पिछले दो वर्षों में 17 हजार करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

डॉ.महापात्रा ने कहा कि सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पिछले कुछ दशकों से लगभग 1 टन प्रति हेक्टेयर हैए जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिये, विस्तार कर्मियों, किसानों, इनपुट डीलरों और सहायक सेवाओं में शामिल अन्य लोगों के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। नई किस्मों का गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में वृद्धि से ही सोयाबीन की उत्पादकता 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

उत्कृष्ट चारा प्रबंधन वाली रानीघाटी गौशाला में लगेगा गौ-संवर्धन योजना प्लांट

स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने किया निरीक्षण

हलधर किसान। मध्यप्रदेश गौ.पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने ग्वालियर जिले के रानीघाटी में गोवर्धन योजना में स्थापित होने वाले गोबर गैस प्लांट स्थल और गौवंश का अवलोकन किया। प्राचीन राम.जानकी परिसर के 1200 बीघा के विशाल भूखण्ड पर स्थित इस गौशाला में लगभग 1200 गौवंश हैं। शीघ्र ही भोपाल से आने वाली तकनीकी टीम द्वारा कार्य.योजना बनाने के बाद गैस प्लांट कार्य करना आरंभ कर देगा।

स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने गौशाला की देखभाल कर रही कृष्णायन सेवा समिति द्वारा उत्कृष्ट गौ.चारा प्रबंधन की भूरि.भूरि प्रशंसा की। उन्होंने मशीन से धान की पराली से तैयार किये गये चारा भूसे के विशाल साइलेज का भी निरीक्षण किया। एक छोटे.मोटे पहाड़ के आकार में समिति द्वारा धान भूसे के मशीन से बंडल बनाकर स्टोर किये गये हैं। गौवंश को थोड़ा सीरा और नमक मिलाकर दिये जाते हैं। आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्टॉक किये जाने से यह पौष्टिक चारा यहाँ के गौवंश के लिये हमेशा उपलब्ध रहता है। हरिद्वार की कृष्णायन देशी गौपालन संस्था में लगभग 65 महात्मा हैं, जो देश के अनेक स्थानों पर बड़ी.बड़ी गौशाला का संचालन कर रहे हैं। इन महात्माओं में इंजीनियर, प्रोफेसर, बैंकिंग सर्विस से सेवानिवृत्त अधिकारी, वैज्ञानिक, कथा.वाचक आदि आध्यात्मिक साधक हैं। स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने ग्वालियर की मशहूर लाल टिपारा गौशाला का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। यह गौशाला पूर्व में अव्यवस्था का शिकार थी। नगर निगम ग्वालियर ने कृष्णायन से अनुबंध किया और आज यह गौशाला आदर्श गौशाला के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है।

यहाँ 5 हजार से अधिक गौवंश हैं। पहले यहाँ रोज 10 से 20 बीमार, बेसहारा गायों की मृत्यु होती थी, जो अब घटकर जीरो हो गई है। ग्वालियर शहर में भी नगर प्रशासन की अनुमति से लगभग 2200 गौवंश की सेवा कृष्णायन संस्था द्वारा की जा रही है। निरीक्षण के दौरान गौशाला प्रबंधन के निदेशक स्वामी ऋषभ देव और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप संचालक केशव सिंह बघेल भी मौजूद थे।

क्या 25 साल बाद भारत में नही होगी खेती!

ईशा फाउंडेशन का चौंकाने वाला सर्वे, सद्गुरू ने कहा कि किसानों की आय डॉक्टर, इंजीनियर, वकील के बराबर होनी चाहिए तभी किसान खेतों में टिक पाएंगे

हलधर किसान। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक व आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने भविष्य में भारत के कृषि क्षेत्र को लेकर चौंकाने वाली बातें कही हैं। सद्गुरु ने कहा है कि अगले 25 साल में भारत में कोई भी किसान नहीं रहेगा। उन्होंने अपने संगठन के एक सर्वे को लेकर यह दावा किया है। सद्गुरु ने आगाह किया कि भारत में कृषि प्रक्रिया को आकर्षक नई बनाई गई तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

भारत में कृषि से जुड़े लोग अपनी जमीन पर रहकर अपना करियर नहीं बना पा रहे। नतीजा यह हुआ कि आज किसानों की 63 प्रतिशत आबादी में से 2 प्रतिशत भी ऐसे नहीं जो भविष्य में कृषि क्षेत्र में बने रहना चाहते हों।

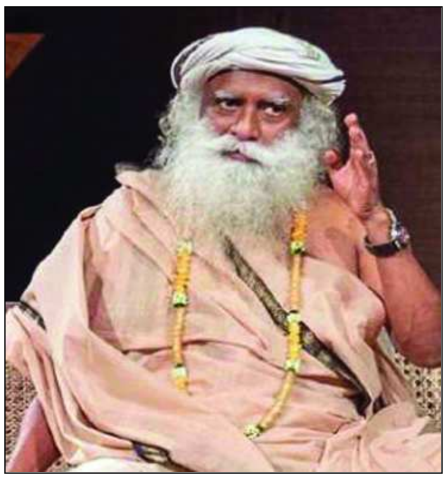

न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के साथ वर्चुअल बातचीत में आध्यात्मिक गुरु व ईशा फाउंडेशन के संस्थापक ने अपने संगठन की ओर से किए गए एक सर्वे के डेटा का जिक्र किया। सद्गुरु ने कहा कि ईशा फाउंडेशन ने इस बात को लेकर एक सर्वे किया है। जिससे यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि अगर सरकार की कृषि नीतियों में बदलाव नहीं आया तो अगले 25 वर्षों में भारत में कोई किसान नहीं होगा। सद्गुरु ने इसके लिए मौजूदा अनिवार्य शिक्षा प्रक्रिया को भी जिम्मेदार माना। हलांकि उन्होंने बालश्रम का समर्थन नहीं किया लेकिन कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली बच्चों को 18 साल की उम्र तक स्कूल जाने के लिए मजबूर कर रही है। जब तक बाल श्रम के मुद्दे हैं बच्चे खेत में काम करने नहीं जा सकते। सद्गुरु ने कहा कि वे बाल श्रम के पक्ष में नहीं हैं लेकिन वे मौजूदा अनिवार्य शिक्षा प्रक्रिया के खिलाफ हैं। सद्गुरु ने कहा कि हमारा शिक्षा का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे देश के मूल सिद्धांत नष्ट न हो जाएं। सद्गुरु ने कहा कि उनके संस्थान ईशा फाउंडेशन की ओर भविष्य में भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति को लेकर एक सर्वे किया गया है। जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए है।

आध्यात्मिक गुरू ने कहा कि सर्वेक्षण से पता चला है कि किसानों की 63 प्रतिशत आबादी में से 2 प्रतिशत भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसान बनें और न ही बच्चे उनके जैसा बनना चाहते हैं। सद्गुरु ने इसे राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि इससे बचने लिए हमें कृषि क्षेत्र को आकर्षक बनाना होगा। किसानों की आय में वृद्धि करनी होगी। सद्गुरु ने कहा कि किसानों की आय डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार के बराबर होनी चाहिए। तभी किसान खेतों में टिक पाएंगे।

भारत 48 सालों के बाद वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी करने जा रहा है, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सितंबर में होगा तीन दिवसीय समिट

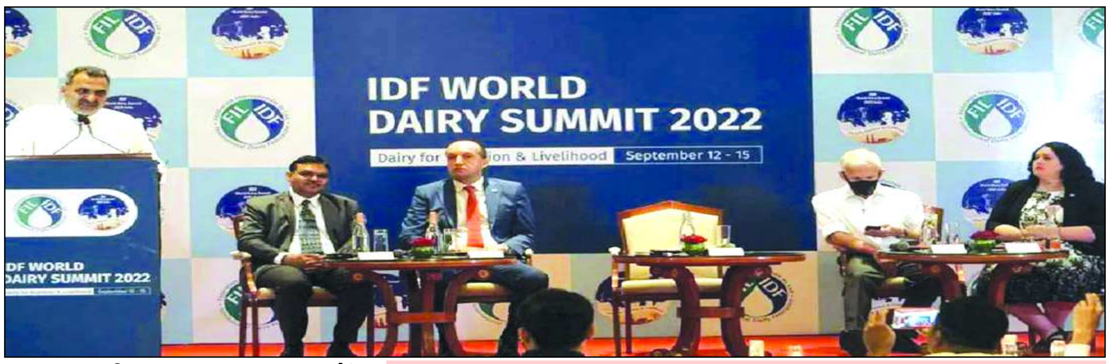

हलधर किसान। भारत 48 सालों के बाद वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी करने जा रहा हैण् जो डेयरी क्षेत्र में काम कर रहे किसानों के साथ डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों के लिए बेहद ही खास माना जा रहा हैण् सम्मेलन में डेयरी महासंघ की तरफसे इस क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

नई दिल्ली में सम्मेलन की घोषणा करने के लिए आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान ने की। उन्होंने कहा कि भारत 48 वर्षों के बाद वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी करने जा रहा है, जो बेहद ही खुशी की बात है। डेयरी सेक्टर में वैश्विक विकास दर सिर्फ दो फीसदी है, जबकि हमारे देश में इसकी विकास दर छह फीसदी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर में भारत के विकास दर में और बढ़ोत्तरी होगी।

भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता विश्व से अधिक

मंत्री बालियान ने कहा कि हमारे देश का वार्षिक दूध उत्पादन 21 करोड़ टन हैण् जो दुनिया में सबसे अधिक है। इसके अनुसार भारत वर्तमान में दूध उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर है। विश्व में दूध की उपलब्धता प्रतिदिन 310 ग्राम है, जबकि हमारे यहां यही उपलब्धता प्रतिदिन 427 ग्राम है। सहकारी संस्थाएं भारत के डेयरी सेक्टर का नेतृत्व करती हैं और यह सेक्टर ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन से जुड़ा हुआ है।

40 से अधिक देशों के डेयरी उद्यमी लेंगे हिस्सा

यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ की तरफसे आयोजित किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 12 से 15 सितंबर को आयोजित होने वाले वर्ल्ड डेयरी समिट में 40 से अधिक देशों के डेयरी उद्यमी भाग लेंगे। सम्मेलन में डेयरी उद्योग को अधिक विकसित करने के तरीकों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के आयोजन की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डा संजीव बालियान, पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष मीनेश शाह और अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ के अध्यक्ष पियरक्रिस्टियानो ब्राजाले की तरफ से की गई।

सम्मेलन में किसानों के लिए भी आयोजित होगा विशेष कार्यक्रम

कार्यक्रम में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष मीनेश शाह ने कहा कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डेयरी सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। यह सेक्टर लगभग आठ करोड़ किसानों को आय के अवसर उपलब्ध कराता है। इसलिए भारत के हितधारकों के लिए वर्ल्ड डेयरी समिट महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत न केवल किसानों, बल्कि भूमिहीन किसानों को भी डेयरी से जोड़ा जाता है, उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड डेयरी समिट का विषय आजीविका और पोषण है और हमारे देश के किसान पशुपालन और डेयरी गतिविधियों से अधिक आय प्राप्त करते हैंण् उन्होंने बताया कि विश्व डेरी शिखर सम्मेलन के पहले दिन उद्घाटन के बाद, हम किसानों के लिए एक विशेष सत्र आयोजित करेंगे क्योंकि हमारे ध्यान के केंद्र में किसान हैं। वहीं पशुपालन व डेयरी विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए भारत को अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ और डेयरी पर भारत आने वाले विश्व के अग्रणी देशों के अनुभव का लाभ मिलेगा।

अग्रणी किसानों को प्रशिक्षण में दी फसल ग्रेडिंग जानकारी

हलधर किसान। राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के तहत संचालित राशमी किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और अजवाइन मल्टीग्रेन ग्रेडिंग प्लांट पर एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज जयपुर द्वारा अग्रणी किसानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कृषि उपनिदेशक कृषि विस्तार चित्तौड़गढ़ शिवराज सिंह जांगिड़, सहायक निदेशक शंकर लाल जाटए कृषि अनुसंधान अधिकारी रमेश चंद्र आमेटा के आतिथ्य में आयोजित हुआ है।

प्रशिक्षण में कृषि उपनिदेशक शिवराज सिंह जांगिड़ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए एफपीओ के माध्यम से फसलों का क्रय.विक्रय करके फसलों को बेचने से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दीण् सहायक निदेशक शंकर लाल जाट ने अजवाइन फसल की वैज्ञानिक ढंग से खेती संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का प्रयोग और उपज का मूल्य का संवर्धन पर तकनीकी जानकारी और फसलों के उचित रखरखाव भंडारणए किस्म में बीज उपचार और पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

बीज अनुसंधान अधिकारी रमेश चंद्र आमेटा ने फसलों की वैज्ञानिक ढंग से खेती संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का प्रयोग और मूल्य संवर्धन पर विस्तृत जानकारी देकर फसलों की प्रोसेसिंग और व्यवसाय और निर्यात के बारे में जानकारी दी। एफपीओ सीईओ और मार्केटिंग मैनेजर रतन लाल कीर ने अजवाइन और मल्टीग्रेन ग्रेडिंग प्लांट का अवलोकन करवाया। सीनियर टेक्नीशियन एग्रो सा कंपनी अंबाला के उम्मेद शर्मा ने अजवाइन मल्टीग्रेन ग्रेडिंग प्लांट पर होने वाले अजवाइन, चना,सरसों, गेहूं, मक्का की फसलों की ग्रेडिंग की जानकारी दी। सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी लालू राम वैष्णव ने मंच संचालन किया। पूर्व लैब इंचार्ज एंड हेड केमिस्ट मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कपासन गोविंद आर्य ने सोयल हेल्थ कार्ड के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में 50 किसानों ने भाग लिया।

ओडिशा में दुग्ध उत्पादको ने की दूध पर एमएसपी की मांग

हलधर किसान। ओडिशा के दूध उत्पादक किसान दूध परएमएसपी कि मांग कर रहे है। इसे लेकर प्रदेश में डेयरी किसानों के एक संगठन ने केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान को ज्ञापन भी सौंपा गया है। डेयरी किसानों ने मांग रखी है कि दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित होना चाहिए।

दरअसल केंद्रीय मंत्री सजीव बाल्यान ओडिशा के दो दिवसीय दौरे के दौरान दुग्ध किसान संघ के अध्यक्ष रबी बेहरा ने उनसे मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने बताया कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत विश्व स्तर पर इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सके, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें दूध का सही रेट मिलना चाहिए ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सकेण् इसलिए बढती महंगाई के चलते दौर में दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित करने कि आवश्कता है। इसके साथ क ही डेयरी उत्पाद निकाय ने मत्स्य पालनए पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री से दूध और अन्य दूध आधारित उत्पादों जैसे पनीर को एकीकृत बाल विकास सेवाओं और मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों में शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाए जाए मिल्क पार्लर

आईसीडीएस योजना बच्चों की देखभाल और विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रमों में से एक मानी जाती है, स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन दिया जाता है, ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। मिड डे मील दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। एसोसिएशन ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिल्क पार्लर स्थापित करने की भी मांग की जिससे बेरोजगार युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा कर सकेण् साथ ही केंद्रीय मंत्री से देश के विभिन्न मंदिरों के परिसरों में दूध हब स्थापित करने की पहल करने का भी आग्रह किया जहां पूजा के लिए डेयरी उत्पाद उपलब्ध करवाए जा सके।

वैज्ञानिकों के तैयार किया गेहूं का नया बीज, 76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की होगी पैदावार

हलधर किसान। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित गेंहूं, सरसों व जई की उन्नत किस्मों का अब हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के अन्य प्रदेशों के किसानों को भी अच्छा लाभ मिल सकेगाण् अब विश्वविद्यालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी क्षेत्र की प्रमुख बीज कंपनी से अब समझौता किया है। ये कंपनी गेंहू की डब्लयूएच 1270, सरसों की आरएच 725 व जई की ओएस 405 किस्मों का बीज तैयार कर किसानों तक पहुंचाएगी ताकि किसानों को उन्नत किस्मों का विश्वसनीय और उच्च गुणवता वाले बीज मिल सके और उनकी पैदावार में इजाफा हो और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। बताया जा रहा है कि गेहूं की इस किस्म में औसत पैदावार करीब 76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी किसानों तक नहीं पहुंचती तब तक उसका कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए इस तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर कर विश्वविद्यालय का प्रयास है कि यहां विकसित फसलों की उन्नत किस्मों के बीज व तकनीकों को अधिक से अधिक देश किसानों तक पहुंचाया जा सके।

किसानों को क्या फायदा होगा

उन्नत किस्म के बीजों से फसलों की अधिक उत्पादन होगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। राज्य व देश की आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत होगी। इसीलिए यूनिवर्सिटी की ओर से पिछले एक साल में विभिन्न प्राइवेट कंपनियों के साथ इस प्रकार के दस एमओयू भी किए जा चुके हैं। ताकि अच्छी किस्म के बीज किसानों तक आसानी से पहुंच सकें। फसलों की इन उन्नत किस्मों के लिए विश्वविद्यालय की ओर से गुरुग्राम की एक निजी कंपनी को तीन वर्ष के लिए गैर एकाधिकार लाइसेंस भी प्रदान किया गया है। जिसके तहत यह बीज कंपनी गेंहू, सरसों व जई की उपरोक्त किस्मों का बीज उत्पादन व मार्केटिंग कर सकेगी। इससे पहले यह कंपनी ज्वार, बाजरा व मूंग की किस्मों के लिए भी विश्वविद्यालय के साथ समझौता कर चुकी है।

क्या है? न किस्मों की खासियत

सरसों की आरएच 725 किस्म की फलियां अन्य किस्मों की तुलना में कुछ लंबी हैं। उनमें दानों की संख्या भी ज्यादा होती है। साथ ही दानों का आकार भी बड़ा होता है और तेल की मात्रा भी ज्यादा होती है।वही गेंहू की डब्ल्यूएच 1270 किस्म को पिछले वर्ष देश के उत्तर दक्षिण जोन में खेती के लिए अप्रुवड किया गया था। इस किस्म की औसत पैदावार 75.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जबकि उत्पादन क्षमता 91.5 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी 12 प्रतिशत है आमतौर पर 50 क्विंटल तक की पैदावार भी प्राप्त होती है। जई की ओएस 405 किस्म देश के सेंट्रल जोन के लिए एकदम उपयुक्त किस्म है। इसकी हरे चारे की पैदावार 51.3 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है जबकि दानों का उत्पादन भी 16.7 प्रति हैक्टेयर है।

देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातें में पहुंची 21 हजार करोड़ से अधिक की राशि, पीएम ने सिंगल क्लिक के जरिये खातों में पहुंचाई राशि

हलधर किसान। खरीफ सीजन से पहले किसान सम्मान निधि की राह तक रहे किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई को शिमला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के जरिये 2-2 हजार रुपए की राशि सीधे बैंक खातों में पहुंचाकर राहत दी है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 10 करोड़ से अधिक किसानों को 21 हजार करोड़ रुपये जारी किए। यह पीएम.किसान योजना के तहत 11वीं किस्त थी। पीएम मोदी शिमला में आयोजित गरीब कल्या सम्मेलन में ि शामिल होने पहुंचे थे।

पीएम ने केंद्र में एनडीए सरकार की आठवीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान पीएम ने कहा कि अभी देश के करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया। पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है।

प्रधान मंत्री कार्यालय के अनुसार, सम्मेलन का प्रयास सरकारी कार्यक्रमों की पहुंच और वितरण को और अधिक कुशल बनाना था ताकि देश के नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जा सके। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद हैं।

इन तारीखों में भेजी जाती हैं किस्तें

बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त की राशि किसानों के खातों में बीती 1 जनवरी 2022 को ट्रांसफर की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को पहली किस्त का पैसा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में दिया जाता है। वहीं, दूसरी किस्त का पैसा 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच मिलता है। जबकि, योजना की तीसरी किस्त का पैसा 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। योजना का लाभ पाने के लिए ईकेवाईसी जरुरी है।

ये किसान रहेंगे लाभ से वंचित

यहां पर यह बताना जरूरी है कि आप भले ही छोटे या फिर सीमांत किसान हों, लेकिन अगर परिवार का कोई सदस्य टैक्स जमा करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहां परिवार के सदस्य से मतलब पति.पत्नी और अवयस्क बच्चों से है। इसके अलावा जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं हो, कृषि योग्य भूमि हो लेकिन इसका मालिक सरकारी कर्मचारी हो या फिर किसान को सालाना 10 हजार रुपये पेंशन प्राप्त होती है, तो ऐसे किसानों को योजना से बाहर रखा गया है।

मध्यप्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के 82 लाख 25 हजार किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 11वीं किशत पहुंची।

7 जून तक चलेगी चना खरीदी, मप्र सरकार ने दी किसानों को राहत

प्रदेश में 871100 मिट्रिक टन चना की खरीद का है लक्ष्य

हलधर किसान। मध्य प्रदेश के चना उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने अब सरकारी चना खरीद कि तारीख को और आगे बढ़ा दी है। ये कल 31 मई को खत्म होनी थी। लेकिन सरकार ने किसानों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए इसे एक सप्ताह के लिए और आगे बढ़ दिया गया है। अब आगामी 7 जून तक सरकार चने की खरीद जारी रखेगी। मुख्यमंत्री शिवराज शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के आग्रह पर ही चना फसल की खरीदी की तिथि आगे बढ़ाई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि चने की फसल फरवरीमें ही तैयार हो जाती थी। लेकिन सरकार इसको गेहूं की खरीद के बाद ही चना खरीद करती थी। ऐसे मे चना किसान औने.पौने दाम पर अपनी फसल बेच देता था। जिससे उसे रेट कम ही मिलता था, लेकिन इस साल सरकार द्वारा ऐसा नहीं होने दिया गया। पटेल ने आगे कहा कि पहले चने की सरकारी खरीद मई में शुरू होती थी। लेकिन इस बार उन्होंने गेहूं से पहले ही इसकी सरकारी खरीद भी शुरू करवा दी थी ताकि किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिले। चने की खरीद से संबंधित सरकार ने कुछ दिनों पहले एक और बड़ा अहम फैसला लिया था। जिसके अनुसार पहले सरकारी मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रोजाना चना खरीदने की सीमा सिर्फ25 क्विंटल थी। लेकिन उसे बढ़ाकर सरकार ने अब 40 क्विंटल कर दिया था। पहले प्रति हेक्टेयर जमीन पर महज 15 क्विंटल चने की सरकारी खरीद होती थी, जिसे 20 क्विंटल तक कर दिया गया था।

और कितनी होनी है खरीद

कृषि विभाग ने सभी कलेक्टरों को नए आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा है कि रबी मार्केटिंग सीजन 2022.23 में चना फसल खरीद की अंतिम तारीख 31 मई के स्थान पर 7 जून 2022 की गई है। इस साल प्रदेश में 871100 मिट्रिक टन चना की खरीद का लक्ष्य रखा है। बता दें कि देश में सबसे ज्यादा चने का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। इसलिए चने की खरीद का वक्त बढ़ाने का आदेश किसानों के लिए काफी मायने भी रखता है। जानकारी के लिए बता दे कि रबी मार्केटिंग सीजन 2022.23 में चने का एमएसपी 5230 रुपए प्रति क्विंटल तय है।

दलहनी फसलों में चने का है बड़ा अहम स्थान

चना रबी सीजन में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। विश्व के कुल चना उत्पादन का करीब 70 परसेंट अकेले भारत में ही होता है। जबकि भारत में सबसे ज्यादा खेती एमपी में ही होती है। यहां देश का लगभग एक चौथाई चना पैदा होता है।

कृषि मंत्री ने किसानों से भी की अपील

चना खरीद की तारीख बढ़वाने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से फसल बीमा करवाने और प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देने की अपील भी की है। राज्य सरकार एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करवाएगी। जैविक खेती में 17 लाख हेक्टेयर एरिया के साथ प्रदेश पहले से ही देश में पहले स्थान पर है।

महाराष्ट्र में इस साल खरीफ फसल का रकबा बढ़ने की उम्मीद

छत्तीसगढ़ में 48 लाख 20 हजार हेक्टेयर में होगी बुआई

हलधन किसान। देशभर में जहां किसान खरीफ सीजन फसलों की बुआई की तैयारियों में जुट गया है, वहीं केंद्र सहित राज्य सरकारें किसानों को खाद, बीज उपलब्ध कराने की तैयारियां पूरी कर रही है।

मौसम विभाग ने इस बार औसत से अधिक बारिश का अनुमान लगाया है। महाराष्ट्र में भी अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की गयी है। इसके बाद से यहा के किसानों के चेहरे खिल गए हैं। कृषि विभाग के मुताबिक इस बार महाराष्ट्र में खरीफ फसलों की बुवाई का रकबा बढ़ने की उम्मीद है, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा।

महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों की वार्षिक खरीफसमीक्षा बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई। समीक्षा बैठक के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग का अनुमान है कि आगामी खरीफसीजन 2022.23 के दौरान राज्य में 158 लाख हेक्टेयर में फसल की बुवाई की जाएगी। जबकि पहले बुवाई का क्षेत्र 155 लाख हेक्टेयर थ। विभाग के अनुमान के मुताबिक इस साल प्रमुख फसलें जैसे दलहन, चना और तिलहन के बुवाई क्षेत्रफ्ल में वृद्धि होगी।

अनुमान लगाया गया है कि इस साल फ्सल और दलहन का उत्पादन 104.55 लाख टन होने की उम्मीद है जबकि पिछले वर्ष इनका उत्पादन 81.6 लाख टन हुआ थाण् इसके अलावा इस खरीफ सीजन में तिलहन का उत्पादन 56.7 लाख टन से बढ़कर 69.7 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री दादा भूसे ने कहा कि आईएमडी ने इस बार राज्य में जल्द ही अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही इस बार बारिश भी जल्दी आ रही है। इसलिए यह साल किसानों के लिए काफी अच्छा रहेगा।

जल्दबाजी में बुवाई नहीं करें किसान

कृषि मंत्री ने आगे कहा कि वो राज्य के किसानों से अपील करते हैं कि किसान जल्दबाजी में खेत में रोपाई या बुवाई नहीं करें, बल्कि अच्छे से बारिश शुरू होने का इंतजार करें। ताकि सूखे कि स्थिति में फ्सल को खराब या बर्बाद होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान जब कोरोना संकट के देश गुजर रहा था उस वक्त भी कृषि क्षेत्र ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में मदद की थी। जबकि उस वक्त सभी सेक्टर धराशायी हो गए थे। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2021.22 में खाद्यान्न के उत्पादन में लगभग 40 फीसदी की वृद्धि देखी गई थी। इसके कारण ही 165 लाख टन का उत्पादन हुआ था। किसानों को परेशानी नहीं हो इसलिए बीज और उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया गया है। उर्वरकों के दाम बढ़ने के कारण कृषि लागत बढ़ गई है। हालांकि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है किसानों पर किसी प्रकार का बोझ नहीं पड़े।

छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया खरीफसीजन की बुवाई का लक्ष्य

जून के पहले सप्ताह से खरीफसीजन के लिए अलग.अलग फ्सलों की बुआई का काम शुरू हो जाएगा। किसान सुविधा तथा भौगोलिक आधार पर खरीफ फसलों की बुवाई करने लगेंगे। खरीफसीजन 2022 के लिए सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में खरीफसीजन की बुवाई के लिए फसलों के बुवाई का लक्ष्य जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के तरफसे जारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में खरीफ2022 में फसलों की कुल बुवाई का रक़बा 48 लाख 20 हजार हेक्टेयर होने जा रहा है, जो पिछले वर्ष से लगभग 55 हजार हेक्टेयर अधिक है। पिछले वर्ष राज्य में खरीफसीजन में कुल 47 लाख 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी। सबसे बड़ी बात है यह है कि किसानों ने धान के बुआई के रकबे में कमी की जाएगी द्य राज्य में खरीफसीजन में पिछले वर्ष के मुकाबले 5 लाख 35 हजार हेक्टेयर की कमी करने का लक्ष्य रखा है।

राज्य सरकार ने धान की खेती छोड़ अन्य फसलों की खेती करने पर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 10 हजार रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दे रही है। योजना का असर राज्य में धान की बुवाई पर पड़ा है। राज्य में बीते खरीफसीजन में 38 लाख 99 हजार 340 हेक्टेयर में धान की बोनी हुई थी द्य इस वर्ष खरीफसीजन में धान की बुवाई का लक्ष्य कम होकर 33 लाख 64 हार 500 हेक्टेयर हो गया है। यानि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 5 लाख 35 हजार हेक्टेयर भूमि में धान की बुवाई कम कर दिया है द्य अन्य फ्सलों का बुवाई का लक्ष्य क्या है ?राज्य सरकार ने राज्य में धान के अलावा अन्य फ्सलों के भी लक्ष्य जारी कर दिए है। खरीफसीजन 2022 में मक्का की बुवाई 3 लाख 14 हजार हेक्टेयर में होगी, जबकि बीते वर्ष राज्य में 2 लाख 5 हजार हेक्टेयर में मक्का लगाया गया था। दो, कुटकी और रागी का रकबा भी 82 हजार हेक्टेयर से बढ़कर एक लाख 47 हजार हेक्टेयर किया गया है। इस प्रकार राज्य में मोटे अनाज का रकबा भी 2 लाख 88 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 4 लाख 60 हजार हेक्टेयर किया गया है। दलहनी फ्सलों का रकबा 4 लाख 48 हजार हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जबकि बीते खरीफसीजन में 2 लाख 77 हजार हेक्टेयर में दलहनी फ्सलों की खेती की गई थी। राज्य में तिलहनी फसलों की बुवाई के रकबे में भी वृद्धि की गई है। इस खरीफसीजन में तिलहनी फसलों की बुवाई का रकबा 2 लाख 67 हजार 700 हेक्टेयर कर दिया गया है। खरीफसीजन 2021 में राज्य में एक लाख 66 हजार 670 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुवाई किया गया था। अन्य फसलों की बुवाई में 1.5 लाख हेक्टेयर में वृद्धि की गई है। वर्ष 2022 में अन्य फ्सल 2 लाख 83 हजार हेक्टेयर लगाए जाने का लक्ष्य है। पिछले वर्ष खरीफसीजन में बोनी का रकबा 1 लाख 33 हजार हेक्टेयर था।

खरीफसीजन में 9000 करोड़ रुपए का लोन वितरित करेगी ओडिशा सरकार

खरीफसीजन में किसानों को खेती करने के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए ओडिशा सरकार ने खरीफसीजन 2022 मे राज्य के किसानों के बीच 9000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है। किसानों को प्राथमिकता के आधार पर लोन दिया जाएगा। खरीफ का सीजन आने वाला है। देशभर के किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए है। खरीफ सीजन किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस सीजन में किसान धान, मकई, सोयाबीन और अन्य खाद्यान्नों की खेती करते हैं।

ओडिशा सरकार के सहकारिता मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर किसानों के बीच लोन का वितरण किया जाए। खरीफफ्सल के लिए ऋण की आवश्यकता वाले किसानों को समय पर ऋण सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं जाएं। फ्सल ऋण वितरण के दौरान छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बटाईदारों और वास्तविक किसानों को संयुक्त देयता समूहों की मदद से फ्सल ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।

किफायती फसलों के लिए प्राथमिकता के आधार पर लोन

सहकारिता मंत्री ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें कृषि कार्य करने में आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। उल्लेखनीय है कि राज्य में किसानों को कुल फ्सल ऋण का 62 प्रतिशत ओडिशा राज्य सहकारी बैंक, राज्य केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। गौरतलब है कि खरीफसीजन 2021 में कुल 18.61.206 किसानों को 8.686.40 करोड़ रुपये का फसल ऋण दिया गया। रबी सीजन 2021.2022 के दौरान सहकारी संस्थाओं ने रिकॉर्ड 7.362.47 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित किया।

खाद की नहीं होगी किल्लत

रबी सीजन में खाद की भयंकर किल्लत झेलने वाले मध्य प्रदेश के किसानों को खरीफ फसलों के लिए राहत की खबर है। मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मांग के मुताबिक खाद उपलब्ध होने पर किसानों को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। प्रदेश में 65 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन और 18 लाख हेक्टेयर में उड़द की बुवाई को देखते हुए डीएपी की जरूरत है। केंद्र सरकार से सूबे को खरीफसीजन.2022 के लिए आवंटन के अनुसार खाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि किल्लत न हो। मंत्री पटेल ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ आयोजित एक बैठक में कहा कि खरीफफसलों के लिए दिए गए माहवार आवंटन के अनुसार 32 लाख मीट्रिक टन उर्वरक समय पर उपलब्ध होने पर किसानों को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। उन्होंने अप्रैल माह के आवंटन के अनुसार शेष एक लाख 13 हजार मीट्रिक टन उर्वरक भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

पटेल ने साथ ही बताया कि प्रदेश में 65 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन और 18 लाख हेक्टेयर में उड़द की बुवाई को देखते हुए डीएपी की आवश्यकता है। एनपीके का लक्ष्य एक लाख से बढ़ाकर ढाई लाख मीट्रिक टन करने की मांग की। उन्होंने किसानों के हित में उर्वरक सब्सिडी एक लाख 62 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख 39 हजार करोड़ करने पर केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया। कहा कि सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 77 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ दिया हैे

जैविक खेती में मध्यप्रदेश नंबर वन

कृषि मंत्री पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश जैविक खेती में देश में पहले पायदान पर है। वर्तमान में देश में 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है, जबकि मध्य प्रदेश में जैविक खेती का रकबा 17.31 लाख हेक्टेयर है। करीब पौने आठ लाख किसान ऐसी खेती कर रहे हैं। जैविक कृषि उत्पादों का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी मध्य प्रदेश से ही हो रहा है। इस वर्ष जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का रकबा और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का भी गठन कर दिया है।

उर्वरक कालाबाजारी पर प्रदेश में कठोर एक्शन होगा

पटेल ने बताया कि खाद की कालाबाजारी करने वालों से प्रदेश में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। किसानों से धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब तक प्रदेश में 22 उर्वरक व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी 1650 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 2501 रुपये कर दी है।

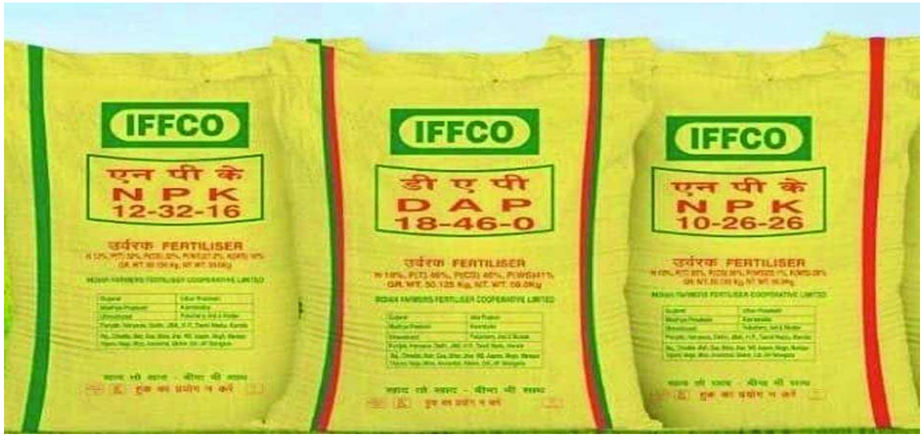

प्रदेश में खरीफ फ्सलों के लिए किसानों को यूरिया, डीएपी सहित अन्य खाद की कमी न आए, इसके लिए सरकार तैयारियों में जुट गई है। तीन लाख 53 हजार टन खाद का भंडारण किया जा चुका है। खरीफसीजन के लिए केंद्र सरकार ने 25 लाख टन खाद उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। प्रदेश को पिछले साल केंद्र ने 12.16 लाख टन यूरियाए छह लाख तीन हजार टन डीएपी और एक लाख 63 हजार टन एनपीके खाद की आपूर्ति की थी।

इसे देखते हुए इस बार 25 लाख टन से ज्यादा खाद की मांग का प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्र सरकार ने 13 लाख टन यूरियाए दस लाख टन डीएपी और दो लाख टन एनपीके की आपूर्ति पूरे सीजन में करने पर सहमति जताई है। वहीं, सरकार ने अग्रिम भंडारण योजना के तहत दो लाख 66 हजार टन यूरिया, 73 हजार टन डीएपी और 13 हजार टन एनपीके का भंडारण करके किसानों को वितरण प्रारंभ कर दिया है।

बीज भण्डार™

भारत में तेजी से बढती हुई रिटेल चैन आउटलेट

सभी कंपनियों के उत्कृष्ट क्वालिटी के बीज मिलने का एक मात्र स्थान

मार्केट मूल्य से कम कीमत पर बीज उपलब्ध

बीज भंडार के सीड कार्ड का विमोचन करते हुए माननीय कृषि मंत्री मध्यप्रदेश शासन श्री कमल जी पटेल एवं खरगोन विधायक श्री रवि जी जोशी

स्मार्ट किसान का स्मार्ट कार्ड सीड कार्ड

आज ही बीज भंडार में अपनी सदस्यता दर्ज कीजिए और पाइए
आपका स्मार्ट कार्ड – सीड कार्ड।
इतना ही नहीं आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के उच्चतम क्वालिटी के बीज और साथ ही अर्जित होंगे आपकी हर खरीदी पर अंक।

इसके अलावा कई उत्पादों पर

आकर्षक और विशेष डिस्काउंट

Seed Card बीज भण्डार™ 78794 28271 | www.beejbhandar.in

डाउनलोड करें : Google play | अधिक जानकारी के लिए YouTube पर देखें : Beej Bhandar, KisanPlusTv | फॉलो :

ब्रांच-खरगोन/खंडवा/ कुक्षी/बडवाह/राजपुर/अंजड/ धामनोद इंदौर/ जबलपुर/ मंडलेश्वर/ मनावर/ बरगी/ कसरावद

बीज भंडार की फ्रेंचाईसी लेने के लिए संपर्क करे - 8305103633, 7879428271

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व प्रधान संपादक विवेक जैन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, बलवंत मार्केट, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित व वार्ड क्र.05, विवेकानंद कॉलोनी से प्रकाशित। Titel Code. MPHIN/2022/37675, मोबा. नं. 9826225 25, 94254 89337, (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)। प्रधान संपादक - विवेक जैन